

प्रेषक,

आर०००के० सुधांशु

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

प्रशिक्षण, विभाग,

उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग

देहरादून : दिनांक ०९ मार्च, 2015

विषय: राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विकासनगर, देहरादून भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10457/डीटीईयू/वृ०नि०प्र०/2014, दिनांक 03 दिसम्बर, 2014, का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभिन्न प्रस्तावों के साथ उपरोक्त विषयगत प्रस्ताव पर कार्यवाही करते हुये धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया था। पत्र के साथ प्रेषित आवासीय भवनों के निर्माण से सम्बन्धित प्रारम्भिक आंगणन रु० 6.28लाख के सापेक्ष टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त रु० 1.40लाख औचित्यपूर्ण पायी है। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-318/XXVII(1)/2014, दिनांक 18 मार्च, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विकासनगर, देहरादून के आवासीय भवनों के निर्माण से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्यों के लिये टी०ए०सी० द्वारा स्वीकृत धनराशि रु० 1.40लाख (रुपये एक लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (2) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 को अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

- (4) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्ये-नजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दसों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (5) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।
- (6) यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।
- (7) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है या वर्तमान कार्य में एक भाग की डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुये तदनुसार कार्यवाही की जाये।
- (8) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कराया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। इसका उत्तरदायित्व निदेशक का होगा।
- (9) एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।
- (10) उक्त कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए इन्हें समयबद्ध ढंग से निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूर्ण जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आगणन के पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (11) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से आवश्यक करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में थर्ड पार्टी चेंकिंग की व्यवस्था की जाय जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय देय सेन्टेज चार्ज के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा गुणवत्ता का समस्त उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी का होगा।
- (12) द्वितीय चरण के विस्तृत आगणन को प्रेषित करते समय यह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाये कि 'प्रथम चरण के प्रस्तावित कार्य पूर्ण हो चुके हैं'।
- (13) आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.06 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला वय्य वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य-आयोजनागत-001-निदेशन तथा प्रशासन- 07-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण-00-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-119(P)/XXVII(1)/2014,दिनांक 27.02.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से ज़रूरी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

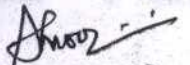
(आर०के० सुधांशु)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल
4. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हल्द्वानी-नैनीताल।
5. निदेशक कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-5/नियोजन विभाग।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विकासनगर, देहरादून।
8. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेजयल संस्थान विकास एवं निगम लि०, देहरादून
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(अनूप कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Technical Education (S051)

आवंटन पत्र संख्या - 08/XLI-1/2015-03/(trg)/15

अनुदान संख्या - 016

अलोटमेंट आई डी - S1503160091

आवंटन पत्र दिनांक - 09-Mar-2015

HOD Name - Director Training (4635)

- 1: लेखा शीर्षक 4216 - आवास पर पूँजीगत परिव्यय 80 - सामान्य
001 - निदेशन तथा प्रशासन 07 - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण
00 - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण

Plan Voted			
मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	50938000	140000	51078000
	50938000	140000	51078000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

140000